Journal Homepage: www.ijarpr.com ISSN: 3049-0103 (Online)

International Journal of Advance Research Publication and Reviews

Vol 03, Issue 9, pp 712-724, September, 2026

स्व-सहायता समूहों का महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण पर प्रभाव: कोंडागांव जिले का अध्ययन

हर्षा मरकाम[1], डॉ. ग्रीष्मा गोपीनाथ के.[2]

[1] **शोधार्थी,** समाजशास्त्र विभाग, कलिंगा विश्वविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)

[2] **शोध-निर्देशक,** समाजशास्त्र विभाग, कलिंगा विश्वविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)

सारांश

स्व-सहायता समूह (Self-Help Groups—SHGs) ग्रामीण भारत में महिलाओं को बचत, ऋण, प्रशिक्षण, सामाजिक नेटवर्क और संस्थागत पहुँच से जोड़ने वाले प्रमुख सामुदायिक मंच बन चुके हैं, पर समूह-सदस्यता को स्वतः सशक्तिकरण मानना समाजशास्त्रीय रूप से पर्याप्त नहीं है। प्रस्तुत अनुभवजन्य अध्ययन कोंडागांव जिले में SHG सदस्यता और महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के बीच संबंध का विश्लेषण करता है। अध्ययन में पीएचडी क्षेत्रीय सर्वेक्षण के 384 महिला उत्तरदाताओं के डेटा का उपयोग किया गया। नमूना चयन में उद्देश्यपरक तथा स्तरीकृत यादृच्छिक नमूनाकरण का संयुक्त प्रयोग किया गया; डेटा साक्षात्कार अनुसूची, प्रश्नावली, फोकस-ग्रुप चर्चा और अवलोकन से संकलित किया गया तथा मात्रात्मक विश्लेषण SPSS में किया गया। कुल 58.85% उत्तरदाता SHG सदस्य थीं। SHG सदस्यों में उच्च सशक्तिकरण का अनुपात 34.96% था, जबकि गैर-सदस्यों में केवल 10.76%; इसके विपरीत निम्न सशक्तिकरण गैर-सदस्यों में 39.24% और सदस्यों में 14.60% था। SHG सदस्यता और समग्र महिला सशक्तिकरण के बीच संबंध सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण था (χ^2=32.47, df=2, p<0.001)। निर्णय-निर्माण में उच्च/मध्यम सहभागिता SHG सदस्यों में 71.24% तथा गैर-सदस्यों में 56.33% रही। बहुविकल्पीय प्रतिगमन में शिक्षा, आय, सामाजिक सहभागिता और निर्णय-निर्माण को नियंत्रित करने के बाद भी SHG सदस्यता सकारात्मक एवं महत्वपूर्ण निर्धारक रही (β=0.16, p=0.004); पूर्ण मॉडल ने सशक्तिकरण में 53% परिवर्तन की व्याख्या की (R^2=0.530)। निष्कर्ष दर्शाते हैं कि SHG प्रभाव केवल ऋण तक सीमित नहीं, बल्कि सामूहिकता, निर्णय-क्षमता, सामाजिक नेटवर्क और संस्थागत संपर्क के माध्यम से प्रकट होता है। तथापि cross-sectional डिजाइन के कारण कारणात्मक निष्कर्ष सावधानी से लिए जाने चाहिए।

मुख्य शब्द: स्व-सहायता समूह; महिला सशक्तिकरण; आर्थिक स्वायत्तता; सामाजिक सहभागिता; निर्णय-निर्माण; आदिवासी महिलाएँ; कोंडागांव; ग्रामीण समाजशास्त्र

1. परिचय

महिला सशक्तिकरण पर विकास विमर्श में पिछले तीन दशकों में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। आरंभिक कार्यक्रमों में महिलाओं की गरीबी को मुख्यतः संसाधनों की कमी, ऋण-अभाव और आय-अवसरों की अपर्याप्तता के रूप में देखा जाता था। इसलिए microcredit, thrift और छोटे उद्यमों को empowerment का प्रमुख साधन माना गया। बाद के समाजशास्त्रीय और नारीवादी अध्ययनों ने स्पष्ट किया कि आर्थिक संसाधन महत्वपूर्ण होने के बावजूद वे तभी सशक्तिकरण में बदलते हैं जब महिला के पास निर्णय लेने, असहमति व्यक्त करने, संसाधनों का उपयोग तय करने, सार्वजनिक क्षेत्र में उपस्थित होने और सामाजिक मानदंडों को चुनौती देने की क्षमता विकसित हो (Kabeer, 1999)। इसी वैचारिक बदलाव ने Self-Help Groups (SHGs) को केवल बचत-ऋण संगठन से आगे बढ़ाकर सामाजिक पूँजी, सामूहिक कार्रवाई और संस्थागत मध्यस्थता के मंच के रूप में समझने की आवश्यकता पैदा की।

कोंडागांव इस प्रश्न के अध्ययन के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जिला प्रशासन के अनुसार जिले की 2011 की आबादी 578,326 थी और अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 405,414 दर्ज की गई, अर्थात लगभग सात-दसवाँ जनसंख्या हिस्सा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है। जिले में 383 ग्राम पंचायत और पाँच जनपद पंचायत हैं; आधिकारिक जिला जनसांख्यिकी पृष्ठ 57.31 प्रतिशत साक्षरता भी दर्ज करता है। यह सामाजिक संरचना SHG प्रभाव के अध्ययन को मुख्यधारा के ग्रामीण microfinance साहित्य से अलग करती है, क्योंकि यहां आजीविका में कृषि, वनोपज, असंगठित श्रम, लघु उद्यम, स्थानीय बाजार और सामुदायिक संबंधों की भूमिका महत्त्वपूर्ण है। जिला पंचायत की आधिकारिक जानकारी राष्ट्रीय आजीविका मिशन/NRLP को स्थानीय ग्रामीण विकास संरचना में संचालित योजना के रूप में सूचीबद्ध करती है। 2022 में जिला प्रशासन ने SHGs की livelihood activities से प्राप्त आय और समावेशन के मूल्यांकन/निगरानी हेतु अभिरुचि आमंत्रित की थी; यह इस बात का संस्थागत संकेत है कि समूह-आधारित आजीविका को जिले में प्रशासनिक महत्व प्राप्त है।

फिर भी स्थानीय नीति-उपस्थिति को empowerment के प्रमाण के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए। समूह बन जाना, बैंक खाता खुल जाना या ऋण मिल जाना अपने आप सामाजिक संबंधों को नहीं बदलता। एक महिला ऋण ले सकती है, लेकिन उसके उपयोग का निर्णय पति या परिवार का अन्य सदस्य कर सकता है। वह आय उत्पन्न कर सकती है, पर कमाई परिवार के नियंत्रण में चली सकती है। वह बैठक में उपस्थित हो सकती है, पर नेतृत्व या सार्वजनिक बोलने की भूमिका न मिले। दूसरी ओर, कई समूह वित्तीय गतिविधि से आगे बढ़कर महिलाओं को ग्राम सभा, पंचायत, बैंक, स्वास्थ्य सेवाओं, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और सामुदायिक मुद्दों में सामूहिक आवाज प्रदान कर सकते हैं। इसलिए SHG का प्रभाव एक binary प्रश्न—"सदस्य है या नहीं"—के बजाय प्रक्रिया संबंधी प्रश्न है: समूह में प्रवेश के बाद कौन-से संसाधन मिलते हैं,

इन संसाधनों पर महिला का नियंत्रण कितना है, समूह किस प्रकार सामाजिक नेटवर्क बनाता है, और क्या यह नेटवर्क घरेलू तथा सार्वजनिक agency में परिवर्तित होता है?

अंतरराष्ट्रीय और भारतीय साक्ष्य इस जटिलता की पुष्टि करते हैं। Brody et al. (2017) की व्यवस्थित समीक्षा ने आर्थिक SHG कार्यक्रमों के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक empowerment पर सकारात्मक प्रभाव पाए, किन्तु प्रभाव के आकार और dimensions में काफी variation था। Deininger and Liu (2013) ने आंध्र प्रदेश में एक SHG मॉडल से महिला सशक्तिकरण और पोषण में लाभ के संकेत पाए, पर आय और asset formation पर स्पष्ट प्रभाव नहीं मिला। Desai and Joshi (2014) के ग्रामीण भारत के अध्ययन में समूह हस्तक्षेप से महिलाओं की household decisions और civic participation में वृद्धि हुई, पर socio-economic status पर असमान परिणाम रहे। Kumar et al. (2021) ने पाँच राज्यों की महिलाओं के panel data में SHG सदस्यता का aggregate empowerment पर सकारात्मक प्रभाव पाया, विशेषकर income control, credit decision और group participation में; फिर भी domestic violence संबंधी attitudes और household respect जैसे गहरे norms में प्रभाव सीमित रहा। ये निष्कर्ष संकेत देते हैं कि SHG एक enabling institution है, न कि empowerment की स्वचालित गारंटी।

वर्तमान लेख इस बहस को स्थानीय अनुभवजन्य डेटा से आगे बढ़ाता है। यह केवल यह नहीं पूछता कि SHG सदस्य महिलाएँ गैर-सदस्य महिलाओं की तुलना में अधिक सशक्त हैं या नहीं, बल्कि यह भी जाँचता है कि SHG सदस्यता का संबंध निर्णय-निर्माण, आर्थिक सक्रियता, व्यक्तिगत आय, सामाजिक सहभागिता और समग्र महिला सशक्तिकरण से किस प्रकार जुड़ता है। कोंडागांव की जनजातीय-बहुल और ग्रामीण सामाजिक संरचना इस प्रश्न को विशेष महत्त्व देती है, क्योंकि यहाँ महिलाओं का श्रम कृषि, वनोपज, हस्तशिल्प, मजदूरी और लघु-उद्यम में व्यापक है, जबकि संसाधनों पर औपचारिक नियंत्रण और सार्वजनिक निर्णय में आवाज समान रूप से वितरित नहीं है।

लेख का empirical आधार 384 महिला उत्तरदाताओं का क्षेत्रीय सर्वेक्षण है। इनमें 226 महिलाएँ SHG से जुड़ी थीं और 158 गैर-सदस्य थीं। इस संरचना से सदस्यता और सशक्तिकरण के बीच तुलनात्मक विश्लेषण संभव हुआ। अध्ययन में सशक्तिकरण को एकल आय या रोजगार सूचक के रूप में नहीं, बल्कि निर्णय-निर्माण, आर्थिक स्वायत्तता, सामाजिक सहभागिता, वित्तीय पहुँच, आत्मनिर्भरता और सार्वजनिक जीवन में भागीदारी के संयुक्त आयाम के रूप में समझा गया है। यही बहुआयामी दृष्टि article की empirical और sociological contribution दोनों का आधार है।

2. समस्या कथन, शोध-अंतर और मौलिकता

SHG साहित्य में सकारात्मक परिणामों की बड़ी संख्या के बावजूद तीन प्रमुख विश्लेषणात्मक समस्याएँ बनी हुई हैं। पहली समस्या आर्थिक उपलब्धि और आर्थिक agency के बीच अंतर से संबंधित है। बचत, ऋण, कारोबार या आय की वृद्धि को empowerment का संकेत माना जाता है, जबकि यह जरूरी नहीं कि महिला उस संसाधन के उपयोग पर नियंत्रण भी रखती हो। ऋण महिला के नाम पर हो सकता है किंतु निवेश का निर्णय परिवार के पुरुष सदस्य द्वारा लिया जा सकता है; समूह गतिविधि से प्राप्त आय household pool में जा सकती है, लेकिन महिला की व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के लिए उपलब्ध न हो। इसलिए income, access to credit और control over income को अलग-अलग मापना आवश्यक है। Kumar et al. (2021) का निष्कर्ष कि SHG प्रभाव का महत्वपूर्ण हिस्सा income control और credit decision से संचालित होता है, इसी distinction को सुदृढ़ करता है।

दूसरी समस्या सामाजिक सशक्तिकरण की संकीर्ण माप से जुड़ी है। कई अध्ययन mobility, household decision-making और meeting attendance को social empowerment के proxy के रूप में उपयोग करते हैं। ये संकेतक महत्त्वपूर्ण हैं, पर सार्वजनिक क्षेत्र में legitimacy, सामूहिक समस्या-समाधान, पंचायत अथवा प्रशासन से बातचीत, entitlement claims और gender norms पर सामूहिक action जैसे पहलू अक्सर छूट जाते हैं। Zavaleta Cheek and Corbett (2024) ने पश्चिम बंगाल के case study में दिखाया कि सार्वजनिक निर्णय-निर्माण में SHGs की वैधता और सामूहिक कार्रवाई—जैसे grain bank तथा शराब-विरोधी mobilization—दीर्घकालिक empowerment की दिशा में महत्वपूर्ण हो सकती है। इससे स्पष्ट होता है कि empowerment केवल household bargaining नहीं; public authority और collective recognition भी उसका भाग है।

तीसरी समस्या स्थानिक और सामाजिक विविधता है। भारत में SHG प्रभाव राज्यों, कार्यक्रम-डिजाइन, जाति/जनजाति, गरीबी स्तर, बाजार संपर्क, समूह की आयु, facilitator की क्षमता और local institutions के अनुसार बदलता है। Brody et al. (2017) ने heterogeneity और programme design की भूमिका को रेखांकित किया। Raghunathan et al. (2019) ने पाया कि SHGs कृषि सूचना और कुछ निर्णयों में सुधार कर सकते हैं, पर improved practices और production outcomes पर प्रभाव सीमित रह सकता है क्योंकि वित्त, gender norms और domestic responsibilities ज्ञान को व्यवहार में बदलने से रोकते हैं। इसलिए दूसरे राज्यों के औसत प्रभाव को Kondagaon पर सीधे लागू करना अनुचित होगा।

कोंडागांव-विशिष्ट शोध-अंतर विशेष रूप से स्पष्ट है। छत्तीसगढ़ में SHG आधारित महिला सशक्तिकरण पर कुछ क्षेत्रीय अध्ययन उपलब्ध हैं, किन्तु कोंडागांव में बड़ी, विविध और जनजातीय-बहुल महिला नमूना आबादी पर SHG सदस्यता को सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तिकरण के संयुक्त सूचक से जोड़ने वाला empirical evidence सीमित है। प्रस्तुत अध्ययन इस कमी को 384 उत्तरदाताओं के क्षेत्रीय डेटा, सदस्य–गैर-सदस्य तुलना, Chi-square परीक्षण और बहुविकल्पीय प्रतिगमन के माध्यम से संबोधित करता है।

लेख की मौलिकता चार स्तरों पर है। पहला, यह SHG को केवल microcredit channel के रूप में नहीं, बल्कि संसाधन, सामाजिक नेटवर्क और agency के बीच सेतु के रूप में देखता है। दूसरा, यह descriptive membership rate से आगे बढ़कर empowerment categories और decision participation के साथ प्रत्यक्ष तुलना प्रस्तुत करता है। तीसरा, बहुविकल्पीय मॉडल यह दिखाता है कि शिक्षा, आय, रोजगार, निवास, जनजातीय स्थिति, सामाजिक सहभागिता और निर्णय-निर्माण को साथ रखने पर SHG सदस्यता का स्वतंत्र सांख्यिकीय संबंध बना रहता है। चौथा, empirical findings को कोंडागांव की tribal-majority, rural-livelihood setting में interpret किया गया है, जिससे aggregate national evidence को local social structure से जोड़ा जा सके।

2.1 अध्ययन के उद्देश्य

कोंडागांव जिले में SHG सदस्यता की व्यापकता और सदस्य महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक प्रोफ़ाइल का वर्णन करना।

SHG सदस्य और गैर-सदस्य महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण स्तर की तुलना करना।

SHG सदस्यता और घरेलू/सामाजिक निर्णय-निर्माण में महिलाओं की सहभागिता के संबंध का विश्लेषण करना।

अन्य सामाजिक-आर्थिक कारकों को नियंत्रित करते हुए महिला सशक्तिकरण के निर्धारकों में SHG सदस्यता के स्वतंत्र योगदान का परीक्षण करना।

SHG आधारित महिला सशक्तिकरण के सामाजिक, आर्थिक और नीतिगत निहितार्थों की समाजशास्त्रीय व्याख्या करना।

2.2 शोध प्रश्न

कोंडागांव में SHG सदस्य और गैर-सदस्य महिलाओं के सशक्तिकरण स्तर में क्या अंतर है?

क्या SHG सदस्यता महिलाओं की निर्णय-निर्माण सहभागिता से सकारात्मक रूप से संबंधित है?

क्या शिक्षा, आय, रोजगार, निवास, जनजातीय स्थिति, सामाजिक सहभागिता और निर्णय-निर्माण को नियंत्रित करने के बाद भी SHG सदस्यता महिला सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण निर्धारक बनी रहती है?

Empowerment के सामाजिक और आर्थिक pathways में कौन-से कारक SHG सदस्यता के प्रभाव को समझने में सबसे अधिक उपयोगी हैं?

2.3 प्रमुख परिकल्पना

H1 (थीसिस की H4 के अनुरूप): महिला सशक्तिकरण में स्व-सहायता समूहों (SHGs) की भूमिका सकारात्मक एवं प्रभावशाली है; अतः SHG सदस्यता और महिला सशक्तिकरण के स्तर के बीच सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण संबंध अपेक्षित है।

3. साहित्य समीक्षा और सैद्धांतिक ढाँचा

3.1 महिला सशक्तिकरण: resources, agency और achievements

Kabeer (1999) का resources–agency–achievements framework महिला सशक्तिकरण को समझने का उपयुक्त आधार प्रदान करता है। इसमें resources केवल धन या संपत्ति नहीं हैं; शिक्षा, कौशल, सामाजिक संबंध, संस्थागत पहुँच और भविष्य के संसाधनों पर दावा भी resources का हिस्सा हैं। Agency में निर्णय-निर्माण के साथ negotiation, resistance, bargaining और strategic choice शामिल हैं, जबकि achievements उन विकल्पों से प्राप्त कल्याण और स्थिति को दर्शाते हैं। इस दृष्टिकोण में किसी resource की empowerment value उसके nominal ownership से नहीं, बल्कि उसके उपयोग की क्षमता और उस उपयोग के सामाजिक अर्थ से तय होती है।

SHG को इसी framework में रखा जाए तो बचत, credit, training और information resources हैं; meeting participation, credit-use decision, leadership, mobility और collective negotiation agency हैं; जबकि आय की स्थिरता, बेहतर consumption security, household respect, public voice और reduced vulnerability achievements हो सकते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि resource से achievement की यात्रा में agency मध्यस्थ होती है। यदि महिला को loan मिला लेकिन निवेश का निर्णय उसके पास नहीं, तो resource आया पर agency सीमित रही। यदि meeting में भागीदारी ने उसे पंचायत में बोलने का आत्मविश्वास दिया, तो group interaction social resource से political agency में बदल गया।

3.2 SHG का संस्थागत विकास: thrift से collective platform तक

भारत में SHGs का प्रारंभिक institutional logic छोटी बचत, आंतरिक ऋण और बैंक linkage पर केंद्रित था। समय के साथ सरकारी और गैर-सरकारी कार्यक्रमों ने समूहों का उपयोग livelihood training, agriculture extension, nutrition, sanitation, health behaviour, public entitlements और governance engagement के लिए करना शुरू किया। यह institutional layering महत्वपूर्ण है क्योंकि empowerment outcome केवल credit availability से नहीं बल्कि SHG के "package" से बनता है। एक समूह केवल monthly saving तक सीमित हो सकता है; दूसरा समूह federation, community resource persons, livelihood collectives और पंचायत linkages से जुड़ा हो सकता है। दोनों को एक ही treatment category मानना causal inference को कमजोर करता है।

3.3 आर्थिक सशक्तिकरण: वित्तीय पहुँच बनाम वित्तीय नियंत्रण

SHG मॉडल का सबसे प्रत्यक्ष pathway financial inclusion है। नियमित बचत से liquidity discipline बनती है; internal lending emergency और small investment needs को पूरा कर सकती है; bank linkage collateral constraints कम कर सकता है; और livelihood loans productive assets अथवा working capital प्रदान कर सकते हैं। किंतु "credit access" और "economic empowerment" के बीच एक महत्वपूर्ण conceptual gap है। Loan महिला के नाम पर होने पर भी उसके उपयोग, repayment burden और profits पर नियंत्रण परिवार के अन्य सदस्यों के पास हो सकता है। इसलिए loan uptake को अंतिम outcome की तरह नहीं, intermediate resource की तरह मापना चाहिए।

Kumar et al. (2021) ने पाँच भारतीय राज्यों की 1,470 ग्रामीण महिलाओं के panel data और matching methods का उपयोग कर SHG membership का aggregate empowerment पर सकारात्मक प्रभाव पाया। यह effect income control, credit-related decision-making और group involvement से संचालित था। महत्वपूर्ण रूप से, अध्ययन ने यह भी पाया कि household respect या domestic violence संबंधी attitudes जैसे domains पर प्रभाव सीमित था। इससे आर्थिक agency की relative responsiveness और gender norms की relative persistence दोनों सामने आती हैं।

Surendran Padmaja et al. (2023) ने 815 households के intra-household survey में women-centric agricultural SHGs का 14 farm और household decisions पर प्रभाव जाँचा। उन्होंने महिलाओं की decision-making role में लगभग 8–13 प्रतिशत वृद्धि रिपोर्ट की, पर effect SHG intervention के प्रकार और decision domain के अनुसार बदलता था। Seed-oriented groups में spousal decision discord microfinance groups की तुलना में कम पाया गया। इससे यह तर्क मजबूत होता है कि SHG design स्वयं empowerment mechanism को प्रभावित करता है; केवल group membership पर्याप्त explanatory variable नहीं है।

Brody et al. (2017) की mixed-methods systematic review ने economic SHGs के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक empowerment पर सकारात्मक प्रभाव दर्ज किए। Qualitative evidence में money handling की familiarity, financial decisions में independence, solidarity, networks और household/community respect प्रमुख mechanisms थे। साथ ही review ने यह भी चेतावनी दी कि सबसे गरीब महिलाएँ आर्थिक, सामाजिक या धार्मिक barriers के कारण groups से बाहर रह सकती हैं। इसलिए SHG programme की inclusiveness भी empowerment evaluation का हिस्सा होनी चाहिए।

3.4 सामाजिक नेटवर्क, mobility और entitlement access

सामाजिक empowerment का एक केंद्रीय dimension घर से बाहर meaningful relationships और institutional contacts का विस्तार है। ग्रामीण पितृसत्तात्मक contexts में महिलाओं की mobility सीमित होने पर bank, block office, पंचायत, health centre या market तक पहुँचना स्वयं agency का संकेत हो सकता है। SHG meeting नियमित और socially legitimate public presence बनाती है। इससे peer ties, information channels और सामूहिक confidence बन सकते हैं।

Kumar et al. (2019) ने पाँच राज्यों के data में SHG membership को social networks, mobility, political participation और public entitlement access से जोड़ा। Matching methods के बाद SHG members राजनीतिक रूप से अधिक engaged थे, कुछ सरकारी योजनाओं के बारे में अधिक जानती थीं और अधिक entitlements का उपयोग करती थीं। यह mechanism महत्वपूर्ण है क्योंकि public programme का benefit केवल eligibility पर निर्भर नहीं करता; information, paperwork, mobility और institutional confidence भी आवश्यक हैं। SHG इन transaction costs को collective रूप से कम कर सकता है।

3.5 सार्वजनिक decision-making और collective agency

SHG empowerment की सबसे परिवर्तनकारी संभावना व्यक्तिगत household outcomes से आगे collective agency में है। Zavaleta Cheek and Corbett (2024) ने West Bengal में process tracing के माध्यम से दिखाया कि समूहों ने trust और solidarity निर्मित की, grain bank जैसी community project को स्वयं संचालित कर legitimacy अर्जित की, और बाद में शराब-निषेध जैसे विवादास्पद मुद्दे पर collective authority का प्रयोग किया। इस case में empowerment "महिला ने घर में क्या खरीदा" से आगे "समुदाय ने महिला समूह को वैध निर्णयकर्ता के रूप में कितना स्वीकार किया" तक विस्तृत होता है।

यह distinction नारीवादी empowerment theory से मेल खाता है, जिसमें "power to" के साथ "power with" का महत्व है। Collective action individual vulnerability को कम कर सकता है क्योंकि अकेली महिला जिस gender norm को चुनौती नहीं दे सकती, समूह सामूहिक रूप से उस पर बातचीत कर सकता है। पंचायत या market actor के सामने एक सदस्य की bargaining position सीमित हो सकती है, पर federation या collective producer group अधिक negotiating power रख सकता है।

3.6 कृषि, सूचना और productive agency

ग्रामीण महिला empowerment का बड़ा हिस्सा agriculture और natural-resource livelihoods से जुड़ा है। Raghunathan et al. (2019) ने लगभग 1,000 महिलाओं के cross-sectional data और nearest-neighbour matching के आधार पर पाया कि SHG participation ने agriculture-related information access और कुछ decisions में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई, पर improved agricultural practices, crop diversity या market orientation पर प्रभाव सीमित था। लेखकों ने financial constraints, social norms और घरेलू responsibilities को संभावित बाधाएँ बताया। यह finding "information is not adoption" समस्या को सामने लाती है।

इसका Kondagaon से सीधा संबंध है। वन तथा कृषि-आधारित livelihoods में महिला knowledge पर्याप्त हो सकती है, किंतु input खरीद, भूमि पर अधिकार, transport, market price negotiation और समय की उपलब्धता उसके नियंत्रण में न हो। इस कारण training के बाद भी behaviour change सीमित रह सकता है। इसलिए livelihood intervention का मूल्यांकन केवल training attendance या knowledge score से नहीं, बल्कि actual resource access, production decision, sale proceeds और market contact से होना चाहिए।

Sahu and Ghosh (2018) के Kanker, Chhattisgarh अध्ययन ने स्थानीय रूप से महत्वपूर्ण evidence दिया। 12 SHGs और 120 respondents पर आधारित अध्ययन में विभिन्न schemes के समूह सदस्यों में overall empowerment improvement पाया गया; leadership और income domains तुलनात्मक रूप से मजबूत थे, जबकि production, resources और time domains में empowerment कम था। यद्यपि sample सीमित था और design causal attribution की अनुमति नहीं देता, findings छत्तीसगढ़ के लिए एक उपयोगी संकेत देती हैं: आर्थिक और नेतृत्व gains के साथ time burden और productive resource control की समस्याएँ बनी रह सकती हैं।

3.7 स्वास्थ्य, पोषण और कल्याण के spillover effects

SHG का सामाजिक प्रभाव livelihood से बाहर भी जाता है। Desai et al. (2020) की mixed-methods systematic review ने भारत में women's groups से संबंधित 99 studies का विश्लेषण किया। Moderate-quality experimental evidence ने कुछ interventions में perinatal practices, neonatal survival, immunisation, dietary diversity और vector-borne disease control जैसे outcomes में सुधार दिखाया। सबसे मजबूत effects उन interventions में थे जो केवल information dissemination नहीं, बल्कि community capability building और mobilisation पर आधारित थे।

Saha (2021) ने NFHS-4 district-level indicators और SHG concentration को जोड़कर पाया कि अधिक SHG concentration वाले जिलों में institutional delivery, iron supplementation, family planning knowledge/usage और house/land ownership जैसे outcomes के odds अधिक थे तथा anaemia के odds कम थे। यह ecological association causal proof नहीं है, फिर भी groups को health and welfare diffusion platform के रूप में देखने का आधार देता है।

3.8 आदिवासी महिला, उद्यमिता और intersectionality

Naveen et al. (2023) ने Odisha के Mayurbhanj district में 111 Santhal tribal women entrepreneurs का अध्ययन किया और entrepreneurship intervention के बाद empowerment indicators तथा family decision-making में सकारात्मक परिवर्तन रिपोर्ट किया। Authors ने education और financial capacity को enterprise growth तथा decision agency के लिए महत्वपूर्ण बताया। यह Kondagaon का प्रत्यक्ष evidence नहीं है, किंतु comparable tribal context में livelihood और decision-making के बीच link की संभावना दिखाता है।

3.9 गहरे लैंगिक मानदंड और empowerment की सीमाएँ

SHG literature में एक recurring finding यह है कि आर्थिक और participatory outcomes अपेक्षाकृत जल्दी बदलते हैं, जबकि gender norms अधिक धीमे बदलते हैं। Kumar et al. (2021) ने empowerment score में gains के बावजूद domestic violence attitudes और respect-related dimensions पर सीमित effects पाए। Brody et al. (2017) ने psychological empowerment पर quantitative evidence को comparatively weak बताया। Raghunathan et al. (2019) ने domestic responsibilities को agricultural adoption की बाधा बताया। ये findings एक महत्वपूर्ण caution देते हैं: महिला की income बढ़ना unpaid care division या male authority को स्वतः पुनर्गठित नहीं करता।

3.10 समूह की परिपक्वता, प्रशिक्षण और federation linkage

इसलिए Kondagaon study में membership duration, meeting regularity, audit quality, bank linkage, VO/CLF membership, training intensity और collective initiatives का record लिया जाना चाहिए। केवल "SHG member: yes/no" variable programme exposure की quality को capture नहीं करेगा।

4. अवधारणात्मक ढाँचा: SHG Resource–Collective Agency–Empowerment Model

इस समीक्षा से एक "SHG Resource–Collective Agency–Empowerment Model" प्रस्तावित किया जा सकता है। मॉडल में SHG participation को एक बहु-स्तरीय institutional exposure माना गया है, जिसके पाँच प्रमुख inputs हैं: वित्तीय संसाधन, ज्ञान/कौशल, peer networks, institutional linkage और collective identity। ये inputs सीधे outcome नहीं बनते; इनके बीच conversion mechanisms कार्य करते हैं। उदाहरणतः credit access तभी economic agency बनता है जब महिला उपयोग का निर्णय ले, profit पर नियंत्रण रखे और market तक पहुँच सके। Peer network तभी social agency बनता है जब उससे mobility, information और public speaking की क्षमता बढ़े।

SHG सदस्यता/सक्रिय सहभागिता → बचत/ऋण + कौशल/सूचना + सामाजिक नेटवर्क + संस्थागत संपर्क → संसाधन पर नियंत्रण + आत्म-प्रभाविता + सामूहिक वैधता → आर्थिक agency + घरेलू निर्णय + सार्वजनिक भागीदारी → सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण।

इस pathway को चार प्रकार के moderators प्रभावित करते हैं। पहला household context—पति/परिवार का समर्थन, परिवार संरचना, marital seniority और unpaid care burden। दूसरा individual context—शिक्षा, आयु, digital literacy, health और previous work experience। तीसरा group context—समूह की आयु, governance, leadership rotation, federation linkage और training intensity। चौथा structural context—market distance, bank access, road/transport, community norms, land/forest resource relations और local state responsiveness।

मॉडल यह भी मानता है कि economic और social empowerment के बीच feedback loop होता है। income control महिला की household legitimacy बढ़ा सकता है; increased mobility बाजार अवसर बढ़ा सकती है; public entitlement access household vulnerability घटा सकता है; collective action स्थानीय services को सुधार सकता है। इसलिए linear "credit → income → empowerment" model की जगह recursive, relational model अधिक उपयुक्त है।

तालिका 1. अध्ययन का अवधारणात्मक ढाँचा

SHG exposure	मध्यवर्ती संसाधन	Agency mechanism	मुख्य outcome
सदस्यता, बैठक, बचत, ऋण	वित्तीय पहुँच, कौशल, सूचना	आय/ऋण पर नियंत्रण, self-efficacy	आर्थिक स्वायत्तता
peer group व federation संपर्क	सामाजिक नेटवर्क, institutional linkage	mobility, public speaking, collective bargaining	सामाजिक सहभागिता
training व livelihood linkage	ज्ञान, market information	उद्यम/काम का निर्णय, संसाधन उपयोग	आय व livelihood क्षमता
सामूहिक बैठक और चर्चा	विश्वास, साझा पहचान	घरेलू व सामुदायिक निर्णय में आवाज	निर्णय-निर्माण सशक्तिकरण

नोट. *यह ढाँचा SHG सदस्यता को परिणाम नहीं, बल्कि संसाधनों को agency में बदलने वाली संस्थागत exposure के रूप में समझता है।*

5. पद्धति

5.1 शोध डिजाइन और डेटा का आधार

प्रस्तुत लेख पीएचडी शोध के क्षेत्रीय अनुभवजन्य डेटा पर आधारित है। मूल शोध में mixed research design अपनाया गया, जिसमें वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक मात्रात्मक दृष्टिकोण को गुणात्मक सामग्री के साथ जोड़ा गया। प्राथमिक डेटा कोंडागांव क्षेत्र की महिला उत्तरदाताओं से सीधे संकलित किए गए; साथ ही सरकारी अभिलेख, आधिकारिक रिपोर्ट, पूर्व शोध, पुस्तकों और संस्थागत दस्तावेजों का द्वितीयक स्रोत के रूप में उपयोग किया गया। इस article का मुख्य empirical analysis मात्रात्मक सर्वेक्षण के N=384 उत्तरदाताओं पर केंद्रित है, क्योंकि SHG सदस्यता, सशक्तिकरण सूचकांक और सांख्यिकीय परीक्षण इन्हीं डेटा पर स्पष्ट रूप से उपलब्ध हैं। FGD, साक्षात्कार और अवलोकन से प्राप्त व्यापक गुणात्मक सामग्री शोध-प्रबंध में संदर्भात्मक व्याख्या के लिए प्रयुक्त हुई; यहाँ कोई ऐसी verbatim quotation प्रस्तुत नहीं की गई है जो उपलब्ध thesis record में प्रत्यक्ष रूप से उद्धृत न हो।

5.2 नमूना चयन और नमूना आकार

अध्ययन में उद्देश्यपरक नमूनाकरण (Purposive Sampling) और स्तरीकृत यादृच्छिक नमूनाकरण (Stratified Random Sampling) का संयुक्त प्रयोग किया गया। उद्देश्यपरक चयन से उन भौगोलिक एवं सामाजिक इकाइयों को शामिल किया गया जो शोध उद्देश्यों के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक थीं, जबकि चयनित स्तरों के भीतर विविध सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमियों की महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए स्तरीकरण और यादृच्छिक चयन का उपयोग किया गया। नमूने में शिक्षित-अशिक्षित महिलाएँ, गृहिणियाँ, कृषि एवं मजदूरी में संलग्न महिलाएँ, SHG सदस्य, महिला उद्यमी और हस्तशिल्प/अन्य आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी महिलाएँ शामिल थीं।

नमूना आकार Cochran (1977) के सूत्र से निर्धारित किया गया। 95% confidence level, 5% margin of error तथा p=q=0.50 के आधार पर न्यूनतम नमूना 384 निर्धारित हुआ। कुल 384 महिला उत्तरदाताओं को पाँच चयनित विकासखंड/प्रशासकीय अध्ययन इकाइयों में योजनाबद्ध रूप से वितरित किया गया। यह sample size समूह तुलना तथा बहुविकल्पीय विश्लेषण के लिए पर्याप्त सांख्यिकीय आधार प्रदान करता है।

5.3 डेटा संकलन उपकरण

प्राथमिक डेटा संकलन का प्रमुख उपकरण पूर्वनिर्धारित साक्षात्कार अनुसूची थी। इसके माध्यम से सामाजिक-जनसांख्यकीय पृष्ठभूमि, परिवार, शिक्षा, रोजगार, व्यक्तिगत आय, आर्थिक गतिविधि, SHG संबद्धता, घरेलू एवं सार्वजनिक निर्णय-निर्माण, सामाजिक सहभागिता, अधिकार-जागरूकता और महिला सशक्तिकरण से संबंधित जानकारी संकलित की गई। कुछ उत्तरदाताओं, विशेषतः SHG से जुड़ी महिलाओं, पंचायत प्रतिनिधियों और शिक्षित प्रतिभागियों से संरचित प्रश्नावली के माध्यम से अतिरिक्त जानकारी ली गई। मूल शोध में focus group discussions तथा प्रत्यक्ष अवलोकन भी शामिल थे, जिनका उद्देश्य सामूहिक अनुभव, बदलती सामाजिक भूमिका, आर्थिक भागीदारी और gender relations को contextualise करना था।

5.4 प्रमुख चर और मापन

इस article में स्वतंत्र चर के रूप में SHG सदस्यता को binary रूप में लिया गया—सदस्य और गैर-सदस्य। समग्र महिला सशक्तिकरण को शोध-प्रबंध में विकसित Women Empowerment Index के आधार पर निम्न, मध्यम और उच्च श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। यह सूचक निर्णय-निर्माण, आर्थिक स्वायत्तता, सामाजिक सहभागिता, वित्तीय पहुँच, आत्मनिर्भरता और सार्वजनिक जीवन में भागीदारी जैसे आयामों को समेकित करता है। सहायक विश्लेषण में शिक्षा, व्यक्तिगत आय, आर्थिक सक्रियता/रोजगार, ग्रामीण-शहरी निवास, जनजातीय स्थिति, सामाजिक सहभागिता और निर्णय-निर्माण स्तर का उपयोग किया गया।

5.5 सांख्यिकीय विश्लेषण

मात्रात्मक डेटा का विश्लेषण SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) के माध्यम से किया गया। वर्णनात्मक विश्लेषण में frequency और percentage, तुलनात्मक विश्लेषण में cross-tabulation, Chi-square test, independent-samples t-test और ANOVA, संबंध विश्लेषण में Pearson correlation तथा समेकित निर्धारकों के परीक्षण में multiple regression का उपयोग किया गया। सांख्यिकीय निर्णय के लिए 0.05 significance level अपनाया गया। इस article में SHG–empowerment संबंध के लिए Chi-square परिणाम, SHG–decision participation तुलना और पूर्ण regression model प्रमुख evidentiary आधार हैं।

5.6 नैतिक और विश्लेषणात्मक सावधानी

प्रस्तुत manuscript में केवल समेकित और अनाम सांख्यिकीय परिणाम उपयोग किए गए हैं; किसी उत्तरदाता की व्यक्तिगत पहचान प्रकाशित नहीं की गई है। उपलब्ध thesis text में institutional ethics approval number स्पष्ट रूप से दर्ज नहीं है, इसलिए journal submission से पहले शोधार्थी को अपने विश्वविद्यालयीय अभिलेख के अनुसार consent/ethical approval statement की अंतिम पुष्टि करनी चाहिए। इसी प्रकार cross-sectional डेटा association को स्थापित करता है, causal impact को नहीं; इसलिए 'प्रभाव' शब्द की व्याख्या सांख्यिकीय संबंध और sociological mechanism के संदर्भ में की गई है, न कि randomized causal effect के रूप में।

6. परिणाम

6.1 उत्तरदाताओं की सामाजिक-आर्थिक प्रोफ़ाइल

अध्ययन में कुल 384 महिलाएँ शामिल थीं। 59.64% उत्तरदाता अनुसूचित जनजाति (ST) से थीं; 74.74% ग्रामीण क्षेत्रों में रहती थीं। आयु-वितरण में 26–35 वर्ष (26.82%) और 36–45 वर्ष (25.00%) सबसे बड़े समूह थे। 13.54% महिलाएँ निरक्षर थीं, जबकि 19.53% स्नातक और 8.60% स्नातकोत्तर या उससे अधिक शिक्षित थीं। 28.91% उत्तरदाता गृहिणी थीं; कृषि और कृषि मजदूरी को मिलाकर 37.76% महिलाएँ सीधे कृषि-आधारित कार्य में थीं। व्यक्तिगत आय के संदर्भ में 28.13% महिलाओं की कोई स्वतंत्र मासिक आय नहीं थी, जबकि शेष उत्तरदाताओं में निम्न और मध्यम आय श्रेणियाँ प्रमुख थीं। यह विविधता SHG सदस्यता के प्रभाव को केवल किसी एक सामाजिक

वर्ग या livelihood category तक सीमित न रखकर व्यापक संदर्भ में देखने की अनुमति देती है।

तालिका 2. नमूने के चयनित सामाजिक-आर्थिक संकेतक (N=384)

सूचक	श्रेणी	N	प्रतिशत
सामाजिक श्रेणी	ST	229	59.64
निवास	ग्रामीण	287	74.74
SHG स्थिति	सदस्य	226	58.85
SHG स्थिति	गैर-सदस्य	158	41.15
व्यक्तिगत आय	कोई आय नहीं	108	28.13
आर्थिक गतिविधि	किसी आर्थिक गतिविधि में नहीं	20	5.21
स्थानीय संस्थागत सहभागिता	सक्रिय	86	22.40

नोट. *आँकड़े पीएचडी क्षेत्रीय सर्वेक्षण की वर्णनात्मक तालिकाओं से लिए गए हैं।*

6.2 SHG सदस्यता की व्यापकता

384 उत्तरदाताओं में 226 महिलाएँ (58.85%) किसी न किसी SHG से जुड़ी थीं और 158 (41.15%) SHG की सदस्य नहीं थीं। नमूने में सदस्य और गैर-सदस्य दोनों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होने से तुलनात्मक विश्लेषण संभव हुआ। कोंडागांव जैसे ग्रामीण और जनजातीय बहुल क्षेत्र में 58.85% membership यह संकेत देती है कि SHG स्थानीय महिला जीवन में एक महत्वपूर्ण संस्थागत interface बन चुका है; फिर भी 41.15% non-membership यह भी दिखाती है कि समूहों की पहुँच सार्वभौमिक नहीं है।

6.3 SHG सदस्यता और समग्र महिला सशक्तिकरण

SHG सदस्यता और Women Empowerment Index की श्रेणियों के cross-tabulation में स्पष्ट अंतर दिखाई दिया। SHG सदस्यों में निम्न सशक्तिकरण 14.60%, मध्यम 50.44% और उच्च 34.96% था। गैर-सदस्यों में निम्न सशक्तिकरण 39.24%, मध्यम 50.00% और उच्च केवल 10.76% था। इस प्रकार उच्च सशक्तिकरण का अनुपात सदस्यों में गैर-सदस्यों की तुलना में तीन गुना से अधिक था, जबकि निम्न सशक्तिकरण गैर-सदस्यों में लगभग ढाई गुना अधिक था। मध्यम श्रेणी दोनों समूहों में लगभग समान रही, जिससे मुख्य विभाजन lower और higher empowerment tails में दिखाई देता है।

तालिका 3. SHG सदस्यता और महिला सशक्तिकरण

SHG स्थिति	N	निम्न सशक्तिकरण (%)	मध्यम (%)	उच्च (%)
SHG सदस्य	226	14.60	50.44	34.96
SHG सदस्य नहीं	158	39.24	50.00	10.76

नोट. *Women Empowerment Index की श्रेणियाँ शोध-प्रबंध के समेकित सशक्तिकरण मापन पर आधारित हैं।*

Chi-square परीक्षण ने इस अंतर को सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण पाया ($\chi^2=32.47$, df=2, $p<0.001$)। अतः SHG सदस्यता और महिला सशक्तिकरण के स्तर स्वतंत्र नहीं हैं। थीसिस की H4—कि महिला सशक्तिकरण में SHGs की भूमिका सकारात्मक एवं प्रभावशाली है—को उपलब्ध सर्वेक्षण परिणामों से सांख्यिकीय समर्थन मिला। यह परिणाम हालांकि स्वयं selection bias को समाप्त नहीं करता: अधिक सक्रिय, शिक्षित या संसाधन-संपन्न महिलाएँ SHG में शामिल होने की अधिक संभावना भी रख सकती हैं। इसलिए association मजबूत है, पर causal attribution सीमित रहना चाहिए।

6.4 SHG सदस्यता और निर्णय-निर्माण सहभागिता

SHG सदस्यता का संबंध household और social decision-making से भी दिखाई दिया। 226 SHG सदस्यों में 161 महिलाओं (71.24%) ने उच्च अथवा मध्यम निर्णय सहभागिता दर्ज की, जबकि 158 गैर-सदस्यों में यह संख्या 89 (56.33%) थी। दोनों समूहों के बीच 14.91 percentage points का अंतर है। यह pattern इस तर्क के अनुकूल है कि नियमित बैठकों, सामूहिक बचत, loan discussion, institutional interaction और peer support के माध्यम से महिलाएँ negotiation और decision confidence विकसित कर सकती हैं।

तालिका 4. SHG सदस्यता और निर्णय-निर्माण सहभागिता

SHG स्थिति	उत्तरदाता	उच्च/मध्यम निर्णय सहभागिता (N)	प्रतिशत
SHG सदस्य	226	161	71.24
SHG सदस्य नहीं	158	89	56.33

नोट. *यह descriptive comparison है; इस विशिष्ट 2×2 तुलना के लिए thesis में अलग inferential test report नहीं किया गया है।*

6.5 आर्थिक आयाम: आय, रोजगार और सशक्तिकरण

SHG संबंध को आर्थिक पृष्ठभूमि से अलग कर देखना पर्याप्त नहीं है। व्यक्तिगत मासिक आय और empowerment score के बीच सकारात्मक सहसंबंध मिला (r=0.46, p<0.001)। जिन महिलाओं की कोई व्यक्तिगत आय नहीं थी, उनका औसत सशक्तिकरण स्कोर 47.8 था; ₹1,000–₹5,000 आय वर्ग में यह 52.6, ₹5,001–₹10,000 में 57.4, ₹10,001–₹20,000 में 63.1, ₹20,001–₹30,000 में 68.7 और ₹30,000 से अधिक में 72.4 था। यह monotonic pattern बताता है कि आर्थिक संसाधन empowerment से महत्वपूर्ण रूप से जुड़े हैं।

आर्थिक रूप से सक्रिय महिलाओं (N=364) का औसत empowerment score 58.9 था, जबकि आर्थिक रूप से निष्क्रिय महिलाओं (N=20) में 46.3; independent-samples t-test ने अंतर को महत्वपूर्ण पाया (t=3.21, df=382, p=0.001)। फिर भी बहुविकल्पीय मॉडल में employment का standardized beta 0.09 और p=0.071 रहा, अर्थात अन्य कारकों को नियंत्रित करने पर simple economic activity स्वतंत्र रूप से महत्वपूर्ण नहीं रही। यह finding समाजशास्त्रीय रूप से महत्वपूर्ण है: 'काम करना' और 'सशक्त होना' समानार्थी नहीं हैं; income control, social participation और decision authority अधिक निर्णायक हो सकते हैं।

6.6 सामाजिक सहभागिता, निर्णय-निर्माण और सशक्तिकरण

सामाजिक सहभागिता के निम्न, मध्यम और उच्च स्तरों के साथ empowerment score क्रमशः 46.8, 57.1 और 68.4 था; ANOVA ने समूह-अंतर को महत्वपूर्ण पाया (F=27.64, p<0.001)। इसी प्रकार decision-making के निम्न, मध्यम और उच्च स्तरों पर औसत empowerment score 44.9, 57.6 और 69.8 रहा। निर्णय-निर्माण और समग्र सशक्तिकरण के बीच Pearson correlation r=0.62 (p<0.001) था, जो अध्ययन के सबसे मजबूत bivariate relationships में से एक है।

इन परिणामों से SHG mechanism की एक संभावित सामाजिक व्याख्या मिलती है। यदि group participation महिलाओं को घर से बाहर नियमित, सामाजिक रूप से वैध meeting space, बैंक/पंचायत संपर्क, collective discussion और information network प्रदान करता है, तो उसका योगदान केवल credit तक सीमित नहीं रहता। निर्णय-निर्माण और सामाजिक सहभागिता का empowerment से मजबूत संबंध इस broader institutional pathway को समर्थन देता है।

6.7 बहुविकल्पीय प्रतिगमन: अन्य कारकों को नियंत्रित करने के बाद SHG प्रभाव

महिला सशक्तिकरण के समेकित निर्धारकों का परीक्षण करने के लिए Women Empowerment Index को dependent variable और शिक्षा, व्यक्तिगत आय, रोजगार, SHG सदस्यता, ग्रामीण–शहरी निवास, जनजातीय स्थिति, सामाजिक सहभागिता तथा निर्णय-निर्माण को independent variables के रूप में रखकर multiple regression model बनाया गया। मॉडल statistically significant था (R=0.728, R^2=0.530, Adjusted R^2=0.520, F=52.84, p<0.001) और empowerment में लगभग 53% variance की व्याख्या करता है।

तालिका 5. महिला सशक्तिकरण के बहुविकल्पीय प्रतिगमन परिणाम

स्वतंत्र चर	Standardized β	p-value	व्याख्या
शिक्षा	0.21	<0.001	सकारात्मक, महत्वपूर्ण
व्यक्तिगत आय	0.18	0.002	सकारात्मक, महत्वपूर्ण
रोजगार	0.09	0.071	गैर-महत्वपूर्ण
SHG सदस्यता	0.16	0.004	सकारात्मक, महत्वपूर्ण
ग्रामीण–शहरी निवास	0.08	0.083	गैर-महत्वपूर्ण
जनजातीय स्थिति	-0.07	0.118	गैर-महत्वपूर्ण
सामाजिक सहभागिता	0.24	<0.001	सकारात्मक, महत्वपूर्ण
निर्णय-निर्माण	0.36	<0.001	सबसे मजबूत सकारात्मक संबंध

नोट. *Model summary: R=0.728; R²=0.530; Adjusted R²=0.520; F=52.84; model p<0.001.*

Regression analysis में decision-making का standardized beta सबसे अधिक (β=0.36) था, उसके बाद सामाजिक सहभागिता (β=0.24), शिक्षा (β=0.21), व्यक्तिगत आय (β=0.18) और SHG सदस्यता (β=0.16) रही। SHG का p=0.004 यह दर्शाता है कि अन्य दर्ज predictors को नियंत्रित करने के बाद भी group membership empowerment से स्वतंत्र सकारात्मक संबंध रखती है। दूसरी ओर employment, residence और tribal status bivariate comparisons में महत्वपूर्ण अंतर दिखाने के बावजूद multivariable model में स्वतंत्र रूप से significant नहीं रहे। यह pattern इस thesis को मजबूत करता है कि empowerment social location का simple additive outcome नहीं, बल्कि resources और agency के बीच relational conversion process है।

7. चर्चा

7.1 SHG membership: association से mechanism की ओर

इस अध्ययन का सबसे प्रत्यक्ष परिणाम SHG सदस्यता और empowerment level के बीच मजबूत सांख्यिकीय association है। उच्च सशक्तिकरण 34.96% सदस्यों में और 10.76% गैर-सदस्यों में पाया गया; χ^2=32.47 और p<0.001 इस विभाजन को chance variation से परे दर्शाते हैं। पर समाजशास्त्रीय महत्व केवल statistical significance में नहीं है। यदि membership का स्वतंत्र beta शिक्षा और income को नियंत्रित करने के बाद भी 0.16 रहता है, तो यह संकेत देता है कि SHG कुछ ऐसे non-income resources भी उपलब्ध कराता है जो empowerment से जुड़े हैं—जैसे peer networks, institutional exposure, collective identity, information और public legitimacy।

यह व्याख्या Kabeer (1999) के resources–agency–achievements framework से मेल खाती है। SHG savings और credit को resource बनाता है, पर resource empowerment तभी बनता है जब महिला उसके उपयोग पर प्रभाव रख सके। Group meeting और collective decision process agency को अभ्यास का स्थान देते हैं; बैंक, पंचायत या livelihood agency से संपर्क institutional navigation बढ़ाता है; और repeated participation household तथा community में महिला की social visibility को बदल सकती है। इसलिए observed effect को 'loan effect' कहना बहुत संकीर्ण होगा।

7.2 निर्णय-निर्माण एक केंद्रीय pathway

SHG सदस्यों में उच्च/मध्यम decision participation 71.24% और गैर-सदस्यों में 56.33% होना उस social mechanism की ओर संकेत करता है जिसे collective agency literature रेखांकित करता है। नियमित समूह बैठक में उपस्थित होना स्वयं किसी household hierarchy को तुरंत नहीं बदलता, लेकिन यह बोलने, सुनने, सहमति बनाने, ऋण उपयोग तय करने, repayment planning और सार्वजनिक संस्थाओं से बातचीत जैसी micro-practices को सामान्य बना सकता है। ये practices domestic negotiation में transfer हो सकती हैं।

Decision-making का empowerment के साथ r=0.62 और regression β=0.36 होना विशेष महत्त्व रखता है। इससे यह तर्क कमजोर पड़ता है कि महिला सशक्तिकरण का मूल अर्थ केवल income generation है। यदि decision authority, social participation और education आय से अधिक explanatory weight रखते हैं, तो SHG programme evaluation को loan volume, repayment rate और enterprise count से आगे बढ़कर voice, control, negotiation और autonomy मापना चाहिए। Desai and Joshi (2014), Kumar et al. (2021) और Surendran Padmaja et al. (2023) के findings भी इसी व्यापक दिशा का समर्थन करते हैं।

7.3 आर्थिक भागीदारी: participation और control के बीच अंतर

कुल sample में economic activity बहुत व्यापक थी; केवल 5.21% महिलाओं ने किसी आर्थिक गतिविधि में भाग न लेने की सूचना दी, जबकि कृषि, कृषि मजदूरी, हस्तशिल्प, लघु-व्यापार और service activity प्रमुख थीं। फिर भी 28.13% महिलाओं की स्वतंत्र व्यक्तिगत आय नहीं थी। यह अंतर ग्रामीण महिला श्रम की एक स्थापित समाजशास्त्रीय समस्या सामने लाता है: महिला productive work में सक्रिय हो सकती है पर cash income, asset ownership या expenditure control में कमजोर स्थिति रख सकती है।

इस अध्ययन में income का empowerment से r=0.46 और β=0.18 का संबंध महत्वपूर्ण है, जबकि employment status multivariate model में non-significant हो जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि काम अप्रासंगिक है; बल्कि employment का quality, remuneration, ownership और control मायने रखते हैं। SHG यदि महिला को केवल unpaid collective labour या household-managed credit से जोड़ता है, तो empowerment सीमित रह सकता है। यदि वही group direct savings, own-account operation, market access और enterprise decision support देता है, तो resource control मजबूत हो सकता है। Brody et al. (2017) और Kumar et al. (2021) इसी distinction को व्यापक भारतीय evidence में रेखांकित करते हैं।

7.4 सामाजिक सहभागिता और सार्वजनिक agency

सामाजिक सहभागिता स्तर के साथ empowerment score 46.8 से 68.4 तक बढ़ना और β=0.24 का multivariate association यह दर्शाता है कि household से बाहर की relational resources महिला की agency में केंद्रीय स्थान रखती हैं। ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में mobility, meeting attendance, पंचायत संपर्क, entitlement knowledge, बैंक या market तक जाना केवल logistical activities नहीं, बल्कि public presence और social recognition के रूप हैं। SHG इस प्रकार 'bridging social capital' विकसित कर सकता है—परिवार के भीतर सीमित network से बाहर संस्थागत और सामुदायिक संबंधों तक पहुँच।

Kumar et al. (2019) ने SHG membership को mobility, political participation और public entitlement access से जोड़ा था; Zavaleta Cheek and Corbett (2024) ने collective public decision-making की legitimacy को empowerment का गहरा रूप बताया। कोंडागांव के परिणाम इस literature को स्थानीय empirical आधार देते हैं: SHG association स्वतंत्र रूप से महत्वपूर्ण है, पर social participation का coefficient उससे भी अधिक है। इससे programme design के लिए स्पष्ट संदेश निकलता है कि successful SHG केवल बचत बैठकों तक सीमित न रहकर federation, पंचायत, banking और community problem-solving से जुड़ना चाहिए।

7.5 जनजातीय और ग्रामीण संदर्भ की व्याख्या

नमूने में 59.64% ST महिलाएँ और 74.74% ग्रामीण महिलाएँ थीं। Bivariate comparisons में tribal women का mean empowerment score 54.1 और non-tribal का 59.8 था (t=-2.31, p=0.021); rural women का mean 54.7 और urban women का 62.8 था (t=-2.94, p=0.004)। किंतु regression model में tribal status (β=-0.07, p=0.118) और rural-urban residence (β=0.08, p=0.083) स्वतंत्र रूप से significant नहीं रहे। यह अंतर substantive रूप से महत्त्वपूर्ण है: observed group differences शिक्षा, आय, social participation और decision-making जैसे proximal resources से mediated हो सकते हैं।

इसलिए 'tribal women are less empowered' जैसा सरल निष्कर्ष उचित नहीं होगा। Tribal identity के भीतर भी education, remoteness, livelihood, family structure, market access और SHG exposure में व्यापक विविधता होती है। इसी प्रकार rural residence स्वयं disadvantage नहीं, बल्कि infrastructure, mobility, schooling, bank access और livelihood structure का proxy हो सकता है। High-quality journal interpretation में social category को deterministic explanation की बजाय structural context के रूप में पढ़ना अधिक उपयुक्त है।

7.6 तुलना: उपलब्ध साहित्य से सामंजस्य और भिन्नता

कोंडागांव findings व्यापक SHG literature के तीन recurring conclusions से मेल खाते हैं। पहला, SHG participation का empowerment से सकारात्मक संबंध होता है, पर effect multidimensional है। Brody et al. (2017) ने economic, social और political dimensions में लाभ के साथ heterogeneity दर्ज की। दूसरा, income/credit access से अधिक महत्त्व control और decision process का है; Kumar et al. (2021) ने income control और credit decision को central mechanism पाया। तीसरा, group intervention के प्रकार का परिणाम पर प्रभाव पड़ता है; Surendran Padmaja et al. (2023) ने agricultural SHGs में decision role gains को intervention-specific पाया।

कोंडागांव का विशिष्ट योगदान यह है कि SHG सदस्यता का significant coefficient ऐसे model में भी कायम है जिसमें education, personal income, employment, residence, tribal status, social participation और decision-making साथ शामिल हैं। साथ ही decision-making और social participation का comparatively stronger association दिखाता है कि local empowerment process को केवल finance-centric framework से समझना अपर्याप्त होगा। यह finding Chhattisgarh के Kanker से Sahu and Ghosh (2018) के उस निष्कर्ष से भी संगत है जिसमें leadership और income domains अपेक्षाकृत मजबूत लेकिन resources और time dimensions कमजोर पाए गए थे।

7.7 कारणात्मक सावधानी और वैकल्पिक व्याख्याएँ

हालाँकि statistical results मजबूत हैं, cross-sectional design के कारण यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि SHG membership ने ही empowerment पैदा किया। Self-selection एक प्रमुख चुनौती है: अधिक motivated, socially connected, financially active या supportive households की महिलाएँ SHG में शामिल होने की अधिक संभावना रख सकती हैं। Reverse causality भी संभव है—पहले से अधिक agency वाली महिलाएँ समूहों में सक्रिय भाग ले सकती हैं। Regression observed covariates को नियंत्रित करता है, पर unobserved differences को पूरी तरह समाप्त नहीं करता।

इसलिए article 'SHG causes empowerment' की जगह 'SHG membership is positively associated with empowerment, including after multivariable adjustment' निष्कर्ष को प्राथमिकता देता है। यह सावधानी empirical integrity के लिए आवश्यक है और findings के policy relevance को कम नहीं करती; बल्कि programme evaluation में stronger longitudinal, matched या quasi-experimental designs की आवश्यकता स्पष्ट करती है।

8. नीति एवं व्यवहारिक निहितार्थ

8.1 Credit से agency indicators की ओर

SHG monitoring को केवल group formation, bank linkage, credit disbursement और repayment तक सीमित नहीं रहना चाहिए। कोंडागांव के data में decision-making और social participation empowerment से strongly जुड़े हैं; इसलिए programme MIS में income control, personal savings operation, household expenditure influence, mobility, public speaking, पंचायत/ग्राम सभा participation और entitlement use जैसे indicators शामिल किए जाने चाहिए। इससे financial inclusion और substantive agency के बीच अंतर स्पष्ट होगा।

8.2 Livelihood-plus और market linkage

SHG सदस्यता का सकारात्मक संबंध तभी अधिक टिकाऊ आर्थिक empowerment में बदल सकता है जब training के साथ market access, product quality, price information, transport, digital payments, enterprise bookkeeping और control over proceeds जुड़े हों। कोंडागांव की कृषि, वनोपज और हस्तशिल्प आधारित आजीविका में producer collectives, value-chain linkage और women-controlled accounts महत्वपूर्ण हो सकते हैं। केवल loan देने से business risk महिला पर स्थानांतरित हो सकता है; livelihood-plus model capacity और market support दोनों प्रदान करता है।

8.3 Social participation और federation strengthening

Social participation का β=0.24 और decision-making का β=0.36 यह संकेत देता है कि SHGs को village organisation, cluster-level federation, ग्राम सभा और स्थानीय सेवा संस्थाओं से जोड़ना empowerment pathway को मजबूत कर सकता है। Leadership rotation, meeting facilitation, public speaking, rights awareness और collective grievance mechanisms programme design का हिस्सा होने चाहिए। इससे समूह की भूमिका thrift unit से community institution में विकसित होती है।

8.4 सबसे कमजोर महिलाओं की समावेशिता

41.15% उत्तरदाता SHG सदस्य नहीं थीं। यह प्रश्न महत्त्वपूर्ण है कि non-membership voluntary है या exclusion, time poverty, family restrictions, distance, documentation, indebtedness या social hierarchy से जुड़ी है। Programme success को केवल existing members के outcomes से नहीं, बल्कि excluded women की profile से भी मापा जाना चाहिए। विशेष outreach युवा विवाहित महिलाओं, विधवाओं, अत्यंत गरीब households, remote hamlets और कमजोर digital/financial literacy वाली महिलाओं के लिए आवश्यक हो सकती है।

8.5 Gender-transformative engagement

SHG की financial success स्वयं unpaid care burden, domestic authority या gender norms को स्वचालित रूप से नहीं बदलती। इसलिए household dialogue, पुरुषों और senior family members के साथ gender-equitable decision-making sessions, time-saving infrastructure और childcare support जैसे measures आर्थिक participation को वास्तविक autonomy में बदलने में सहायक हो सकते हैं। Deep norms को programme outcome के रूप में अलग मापना चाहिए, न कि income gain से infer करना चाहिए।

9. ज्ञान में योगदान

यह अध्ययन SHG literature में स्थानीय empirical contribution प्रदान करता है क्योंकि यह tribal-majority Kondagaon में member–non-member comparison को multidimensional empowerment और regression framework से जोड़ता है। सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि SHG membership का independent association (β=0.16, p=0.004) social participation और decision-making जैसे agency variables के साथ सह-अस्तित्व रखता है। इससे SHG को एक standalone treatment की बजाय institutional platform के रूप में conceptualise करना अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है।

अध्ययन यह भी दिखाता है कि social और economic empowerment को अलग compartments में नहीं बाँटा जा सकता। Income और economic activity resources प्रदान करते हैं; social participation networks और institutional access देता है; decision-making इन संसाधनों को agency में बदलता है। SHG इन dimensions के बीच interaction को facilitate कर सकता है। इस relational interpretation से 'loan received' और 'woman empowered' के बीच theoretical दूरी स्पष्ट होती है और evaluation को अधिक rigorous बनाती है।

10. अध्ययन की सीमाएँ

अध्ययन cross-sectional है; इसलिए causality स्थापित नहीं की जा सकती और self-selection bias संभव है।

इस manuscript में respondent-level raw dataset का पुनः स्वतंत्र re-analysis नहीं किया गया; statistical values पीएचडी thesis में रिपोर्ट किए गए field outputs से लिए गए हैं। Journal submission से पहले scholar को original SPSS/Excel dataset से tables और test statistics का final audit करना चाहिए।

SHG membership binary variable group maturity, meeting attendance, loan size, federation linkage और training intensity की heterogeneity को पूर्ण रूप से capture नहीं करता।

Women Empowerment Index समेकित construct है; journal reviewers के लिए इसकी item composition, scoring और reliability statistics को raw instrument के आधार पर अलग methodological appendix में देना उपयोगी होगा।

Qualitative component मूल PhD design में मौजूद है, पर इस article में verbatim respondent quotations का उपयोग नहीं किया गया क्योंकि उपलब्ध thesis text से उनका सुरक्षित और सटीक attribution सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

11. भविष्य के शोध की दिशाएँ

आगे longitudinal design SHG joining से पहले और बाद के बदलावों को पकड़ सकता है। Member और comparable non-member women की baseline-follow-up tracking, propensity score matching या phased programme rollout self-selection bias को कम कर सकते हैं। Group maturity, training intensity, market linkage और federation participation को exposure intensity के रूप में शामिल करना चाहिए।

Economic empowerment के लिए केवल income amount नहीं, income control, savings ownership, loan-use decision, asset acquisition और enterprise revenue control मापे जाने चाहिए। Social empowerment के लिए mobility, public speaking, network breadth, household decision influence, entitlement use और ग्राम सभा participation उपयोगी indicators होंगे। Time-use diaries unpaid care burden और livelihood participation के hidden cost को सामने ला सकते हैं।

Tribal contexts में local-language qualitative interviews और community-specific livelihood mapping विशेष महत्त्व रखते हैं। Forest produce value chains, handicraft markets, land/forest rights, digital finance और women producer groups के साथ SHG linkage पर अलग analyses स्थानीय policy relevance बढ़ा सकते हैं। पुरुष household members और SHG facilitators के interviews से household negotiation तथा institutional mechanism की अधिक संतुलित तस्वीर मिल सकती है।

12. निष्कर्ष

कोंडागांव के 384 महिला उत्तरदाताओं के क्षेत्रीय सर्वेक्षण से SHG सदस्यता और महिला सशक्तिकरण के बीच स्पष्ट, सकारात्मक और सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण संबंध सामने आया। 58.85% उत्तरदाता SHG सदस्य थीं। उच्च सशक्तिकरण 34.96% सदस्यों में और 10.76% गैर-सदस्यों में पाया गया, जबकि निम्न सशक्तिकरण सदस्यों में 14.60% और गैर-सदस्यों में 39.24% था। Chi-square परीक्षण ने संबंध को महत्वपूर्ण पाया ($\chi^2=32.47$, $p<0.001$), और बहुविकल्पीय मॉडल में SHG सदस्यता अन्य सामाजिक-आर्थिक कारकों के नियंत्रण के बाद भी महत्वपूर्ण रही ($\beta=0.16$, $p=0.004$)।

साथ ही, empirical pattern यह स्पष्ट करता है कि SHG effect को केवल वित्तीय संसाधनों से नहीं समझा जा सकता। Decision-making participation SHG सदस्यों में अधिक थी; social participation और decision-making दोनों empowerment के शक्तिशाली predictors थे; और simple employment status multivariate model में स्वतंत्र रूप से significant नहीं रहा। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि meaningful empowerment संसाधन प्राप्ति से आगे resources पर control, social networks, institutional presence और decision authority के विस्तार से बनता है।

अतः कोंडागांव में SHGs को केवल microfinance mechanism के रूप में नहीं, बल्कि आर्थिक संसाधनों को सामाजिक और निर्णयात्मक agency में बदलने वाली सामुदायिक संस्था के रूप में देखना अधिक उपयुक्त है। Programme policy को credit delivery से agency measurement, livelihood-plus support, federation strengthening, public participation और gender-transformative practice की ओर बढ़ना चाहिए। फिर भी causal claims के लिए longitudinal और stronger comparative research आवश्यक है। यह empirical article इसी दिशा में एक district-specific sociological evidence base प्रदान करता है।

संदर्भ

Cochran, W. G. (1977). Sampling techniques (3rd ed.). John Wiley & Sons.

Brody, C., de Hoop, T., Vojtkova, M., Warnock, R., Dunbar, M., Murthy, P., & Dworkin, S. L. (2017). Can self-help group programs improve women's empowerment? A systematic review. Journal of Development Effectiveness, 9(1), 15–40. https://doi.org/10.1080/19439342.2016.1206607

Deininger, K., & Liu, Y. (2013). Economic and social impacts of an innovative self-help group model in India. World Development, 43, 149–163. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2012.09.019

Desai, R. M., & Joshi, S. (2014). Collective action and community development: Evidence from self-help groups in rural India. The World Bank Economic Review, 28(3), 492–524. https://doi.org/10.1093/wber/lht024

Desai, S., Misra, M., Das, A., Singh, R. J., Sehgal, M., Gram, L., Kumar, N., & Prost, A. (2020). Community interventions with women's groups to improve women's and children's health in India: A mixed-methods systematic review of effects, enablers and barriers. BMJ Global Health, 5(12), e003304. https://doi.org/10.1136/bmjgh-2020-003304

District Administration Kondagaon. (2026). About district. Government of Chhattisgarh. https://kondagaon.gov.in/en/about-district/

District Administration Kondagaon. (2026). Demography. Government of Chhattisgarh. https://kondagaon.gov.in/en/demography/

District Administration Kondagaon. (2026). Jila Panchayat. Government of Chhattisgarh. https://kondagaon.gov.in/en/zp/

Kabeer, N. (1999). Resources, agency, achievements: Reflections on the measurement of women's empowerment. Development and Change, 30(3), 435–464. https://doi.org/10.1111/1467-7660.00125

Kumar, N., Raghunathan, K., Arrieta, A., Jilani, A., Chakrabarti, S., Menon, P., & Quisumbing, A. R. (2019). Social networks, mobility, and political participation: The potential for women's self-help groups to improve access and use of public entitlement schemes in India. World Development, 114, 28–41. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.09.023

Kumar, N., Raghunathan, K., Arrieta, A., Jilani, A., & Pandey, S. (2021). The power of the collective empowers women: Evidence from self-help groups in India. World Development, 146, 105579. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2021.105579

Ministry of Rural Development, Government of India. (2024). State performance report 2023–2024. https://rural.gov.in/

Naveen, S., Parida, J. K., & Panda, I. (2023). Tribal women empowerment through entrepreneurship: Evidence from Mayurbhanj District, Odisha. Frontiers in Sociology, 8, 1158770. https://doi.org/10.3389/fsoc.2023.1158770

Raghunathan, K., Kannan, S., & Quisumbing, A. R. (2019). Can women's self-help groups improve access to information, decision-making, and agricultural practices? The Indian case. Agricultural Economics, 50(5), 567–580. https://doi.org/10.1111/agec.12510

Saha, S. (2021). Does membership in women's group advance health and empowerment? Evidence from India. Journal of Family Medicine and Primary

Care, 10(5), 1829–1834. https://doi.org/10.4103/jfmpc.jfmpc_1841_20

Sahu, B. L., & Ghosh, S. (2018). Influence of SHGs on empowerment of rural poor in Chhattisgarh. Journal of Agricultural Extension Management, 16(2), 51–65. https://epubs.icar.org.in/index.php/JAEM/article/view/84975

Surendran Padmaja, S., Korekallu Srinivasa, A., Trivedi, P., & Srinivas, K. (2023). Women self-help groups and intra-household decision-making in agriculture. Annals of Public and Cooperative Economics, 94(3), 857–876. https://doi.org/10.1111/apce.12442

Zavaleta Cheek, J., & Corbett, P. E. (2024). Public decision making by women's self-help groups and its contributions to women's empowerment: Evidence from West Bengal, India. World Development Perspectives, 33, 100549. https://doi.org/10.1016/j.wdp.2023.100549

घोषणा एवं डेटा संबंधी टिप्पणी

यह manuscript Harsha Markam के पीएचडी क्षेत्रीय अध्ययन से व्युत्पन्न है। प्रस्तुत सांख्यिकीय मान शोध-प्रबंध में रिपोर्ट किए गए field outputs पर आधारित हैं। Journal submission से पहले original respondent-level dataset, codebook, SPSS output, consent/ethics documentation और block-level coding का final verification शोधार्थी द्वारा किया जाना चाहिए।